



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 फरवरी 2016—माघ 19, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2016

क्र. एफ-17-09-2001-एक-4.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अक्टूबर 2012 के अनुक्रम में मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (क्रमांक 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, ई.एम.ई. सेन्टर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल को ग्राम सूखी सेवनिया (कल्याणपुर, पिपलिया जाहिरपीर) में निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्धारित करता है, जिसके भीतर 1 अक्टूबर 2015 से प्रारंभ होने वाले तथा दिनांक 30 सितम्बर 2018 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की कालावधि के लिये नियतकालिक रूप से मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास का किया जाना प्राधिकृत किया जा सकेगा :—

1. सेना सुरक्षा विभाग अपनी भूमि पर ही सैन्य अभ्यास कर सकेगा.
2. सेना सुरक्षा विभाग को फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 एवं मध्यप्रदेश सैन्य चालन मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम, 1964 में दर्शाये नियमों का पालन करना होगा.
3. एक्सल्यूट सेफ्टीजोन के अन्तर्गत दर्शायी गई भूमियों में सैन्य अभ्यास के दौरान कम से कम जन-धन हानि हो इसका प्रयास सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा.
4. अभ्यास के दौरान सार्वजनिक आवागमन बन्द नहीं होगा, मध्यप्रदेश सैन्य चालन, मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 12 से 15 अनुसार जो निजी भूमियां प्रभावित होंगी (फसलें) उनका प्रतिकर क्षति होने पर सुरक्षा विभाग को अदा करना होगा, अभ्यास दिवस में आवागमन बन्द किये जाने की स्थिति में आवागमन के रास्तों पर सेना का पहरा लगाया जाकर आवागमन पूर्व से ही बन्द करना होगा.

5. उक्त फील्ड फायरिंग रेंज में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू नहीं होते, परन्तु वन संरक्षण की दृष्टि से फायरिंग रेंज के सेफ्टीजोन में बड़े वृक्षों के साथ छोटे वृक्षों का वृक्षारोपण सेना सुरक्षा विभाग को विभिन्न चरणों में पूरा करना होगा ताकि वृक्षारोपण कॉम्पेक्ट बने और क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कम हो.
6. फायरिंग के दौरान वन सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा, इस दौरान कोई हानि होती है तो नियमानुसार मुआवजे का भुगतान, सेना सुरक्षा विभाग को करना होगा.
7. मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास के दौरान जन-हानि, पशु हानि, फसल की हानि होने पर सुरक्षा विभाग को नियमानुसार मुआवजे का भुगतान करना होगा, उक्त रेंज के अन्तर्गत एवं आसपास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग आफीसर की होगी.
8. सेना सुरक्षा से लिखित वचन-पत्र लिया जावे कि भारत सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा भविष्य में भी यदि कोई शर्तें निर्धारित की जाती है तो उन शर्तों को मानने के लिये उक्त विभाग बाध्य होगा.
- (9) भू-रेखांक एवं क्षेत्र के ब्यौरे संबंधी अनुसूची का निरीक्षण कलेक्टर, भोपाल के कार्यालय में किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आनंद कुमार शर्मा, अपर सचिव.